सवाल जवाब

अगले 4-5 वर्ष में भारत होगा सबसे आकर्षक शेयर बाजार

जैसे-जैसे वैश्विक निवेशक दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं, भारतीय इक्विटी की रैंकिंग नीचे खिसक गई है। मॉर्गन स्टैनली के प्रबंध निदेशक और मुख्य इक्विटी रणनीतिकार (भारत) रिधम देसाई का कहना है कि भारत को लेकर जो निराशा का माहौल है, वह पूर्ण विकास के बजाय सापेक्ष वृद्धि से ज्यादा जुड़ा है। मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 से पहले मुंबई में समी मोडक और सुंदर सेतुरामन के साथ एक साक्षात्कार में देसाई ने तर्क दिया कि निवेशकों का रुख अत्यधिक मंदी वाला हो गया है। लेकिन जल्द ही नजरिया सकारात्मक होना शुरू हो सकता है। बातचीत के मुख्य अंश:

विदेशी ब्रोकरेज और निवेशकों के बीच भारत को लेकर निराशा बढ़ती दिख रही है। इस धारणा का क्या कारण है?

यह निराशा मोटे तौर पर भारत की सापेक्ष वृद्धि को लेकर है, न कि उसकी निरपेक्ष वृद्धि को लेकर। पिछली दो तिमाहियों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। लेकिन अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यहां तक कि जापान जैसे बाजारों की तुलना में इसकी वृद्धि अभी भी उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। इस समय वैश्विक वृद्धि को जो चीज आगे बढ़ा रही है, वह है एआई की अगुआई में भारी निवेश का दौर, विशेष रूप से डेटा केंद्रों, सेमीकंडक्टर, मेमरी चिप, ऊर्जा सुविधाओं और निर्माण के क्षेत्र में। उम्मीद है कि अमेरिका की शीर्ष तकनीकी दिग्गज कंपनियां इस साल पूंजीगत व्यय पर लगभग 800 अरब डॉलर और अगले साल 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक खर्च करेंगी।

वृद्धि के अलावा भारत में निवेशक धारणा किससे प्रभावित हो रही है?

दूसरी बड़ी चिंता भारत के सेवा निर्यात मॉडल के लिए एआई के कारण होने वाली संभावित उथल-पुथल है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सेवा निर्यात पर निर्भर है और दुनिया भर में धारणा बढ़ रही हैकि एआई इस काम का बड़ा हिस्सा हथिया सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार से सहमत नहीं हूं। लेकिन बाजार अभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एआई से भारत की मध्यम से लंबी अवधि की वृद्धि की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) पैसा बाहर ले जा रहे हैं और घरेलू कंपनियां विदेश में निवेश बढ़ा रही हैं।

ये चिंताएं कुछ समय की हैं या फिर बरकरार रह सकती हैं?

एआई पूंजीगत खर्च चक्र कुछ समय तक रह सकता है। हालांकि भारत के सेवा निर्यात से जुड़ी चिंताएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि डेटा कुछ और ही साबित करने लगेंगे। असल में, अप्रैल के सेवा निर्यात के आंकड़ों ने चौंकाया है और वैश्विक टेक्नॉलजी कंपनियां भारत में लगातार हायरिंग बढ़ा रही हैं। इससे पता चलता है कि वे अब भी भारत को बड़े पैमाने पर कुशल टैलेंट के लिए सबसे अच्छी जगह मानती हैं। मेरा अपना मानना है कि एआई भारत के सेवा क्षेत्र के लिए खतरा बनने के बजाय असल में एक बड़ा अवसर बन सकता है।

आप अगले एक साल में कमाई में बढ़ोतरी के रुझान को किस तरह देख रहे हैं?

भारत ने पिछले साल कर कटौती, दर कटौती और तरलता समर्थन के जरिये कई प्रोत्साहन दिए। आय पर अब इनका असर दिखना शुरू हो गया है और भविष्य में इसमें और मजबूती आनी चाहिए। अगर पश्चिम एशिया संकट लंबा नहीं खिंचा तो वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भारत की वृद्धि दर का अंतर कम हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ तो पूंजी की निकासी कम हो जानी चाहिए और भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होना चाहिए। दिलचस्प यह है कि जहां एक ओर विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी बेच रहे हैं, वहीं पिछले कुछ महीनों में विदेशी ऋण प्रवाह सकारात्मक बना हुआ है। ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में भारत का शामिल किए जाने की संभावना एक महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कारक है।

मौजूदा मूल्यांकन पर भारतीय इक्विटी बाजार कितने आकर्षक हैं?

जब मैं भारत के सापेक्ष मूल्यांकन को देखता हूं, तो ये मेरे 35 साल के करियर में अब तक के सबसे कम स्तर पर है। पिछले 12 महीनों का सापेक्ष प्रदर्शन भी सबसे कमजोर रहा है और विदेशी निवेशकों की स्थिति 16-17 साल के निचले स्तर पर है। इसीलिए मेरा मानना है कि बाजार भारत को लेकर जरूरत से ज्यादा निराशावादी हो गया है।

इसके विपरीत नजरिये से देखें, तो आमतौर पर यही वह समय होता है जब निवेशकों को सकारात्मक रुख अपनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप लंबी अवधि, मान लीजिए चार से पांच साल, का नजरिया रखते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे आकर्षक मूल्यांकन वाला इक्विटी बाजार है।

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से

छोटे शहरों के फंड निवेशकों की परख

अभिषेक कुमार
मुंबई, 1 जून

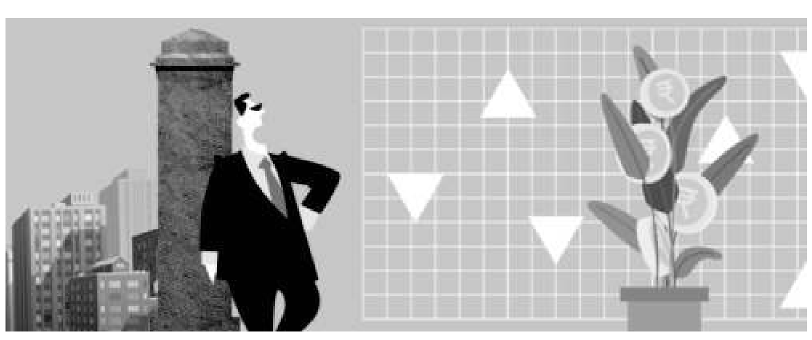

विनय सिन्हा

मार्च-अप्रैल में ऐक्टिव सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) खातों में आई गिरावट का मुख्य कारण निवेशकों का एक खास वर्ग था। इन दो महीनों के दौरान म्युचुअल फंड उद्योग के डायरेक्ट प्लान बी-30 (टॉप 30 शहरों को छोड़कर) एसआईपी खातों में 3,50,000 से ज्यादा की कमी आई। बाकी हिस्सों में स्थिति काफी हद तक स्थिर रही या बढ़ोतरी जारी रही।

फंड निवेशकों का आधार मोटे तौर पर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। देश के जिन 30 शहरों में फंड परिसंपत्तियां सबसे ज्यादा हैं, वहां के निवेशकों को टी-30 निवेशक कहा जाता है। बाकी सभी निवेशक बी-30 श्रेणी में आते हैं। निवेशकों को उनके निवेश के तरीके के आधार पर भी बांटा जाता है - रेग्युलर प्लान (जो बिचौलियों के जरिये बेचे जाते हैं और जिन पर कमीशन मिलता है) और डायरेक्ट प्लान (जो सीधे फंड हाउस से खरीदे जाते हैं)।

कोविड के बाद एसआईपी खातों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, पर हाल के महीनों में उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण शायद शेयर बाजारों में लंबे समय से जारी उतार-चढ़ाव का निवेशकों के मूड पर असर हो सकता है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक दो महीने की इस अवधि में कुल ऐक्टिव एसआईपी खातों की संख्या में 1,14,000 की गिरावट आई है। लेकिन निवेशकों के दोनों वर्गों में रुझान काफी अलग-अलग रहे। जहां टी-30 रेग्युलर प्लान सेगमेंट में इस दौरान 3,13,601 नए खाते जुड़े, वहीं बी-30 डायरेक्ट सेगमेंट में 3,50,000 से ज्यादा खाते कम हो गए। इस गिरावट ने पिछली बढ़त को पूरी तरह खत्म कर दिया और उद्योग के कुल खातों की संख्या को नीचे कर दिया। टी-30 के डायरेक्ट प्लान खातों में भी लगभग 72,000 की गिरावट आई।

म्युचुअल फंड अधिकारियों का कहना है कि यह रुझान उम्मीद के मुताबिक ही है क्योंकि डायरेक्ट प्लान में निवेश करने वाले लोग, खासकर वे जिन्होंने हाल के वर्षों में निवेश शुरू किया है, बाजार के उतार-चढ़ावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

मिरे ऐसेट एमएफ में वितरण और रणनीतिक गठजोड़ की प्रमुख सुरंजना बड़ठाकुर ने कहा, हाल के वर्षों में म्युचुअल फंडों में आने वाले नए निवेशकों का बड़ा हिस्सा बी-30 शहरों का है और उनमें से कई लोग सीधे या बिना किसी मदद के आए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग महामारी के बाद बाजार में आई जबरदस्त तेजी को देखकर अच्छे रिटर्न की उम्मीद से आए हों और हाल के उतार-चढ़ाव की वजह से इन निवेशकों का एक हिस्सा अपनी एसआईपी बंद करने के बारे में सोच रहा हो।

मार्च में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 12 फीसदी गिर गए थे। यह मार्च 2020 के बाद उनकी सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी। इसका कारण पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच तेल की कीमतों में इजाफा था। एडलवाइस फंड के अध्यक्ष व बिक्री प्रमुख दीपक जैन ने कहा, बाजार में उतार-चढ़ाव के दौर में निवेशकों, खासकर जो युवा हैं या पहली बार बाजार में कदम रख रहे हैं, का चिंतित होना पूरी तरह स्वाभाविक है। बाजार के चक्र को समझना एक सीखने की प्रक्रिया है, जिससे हर अनुभवी निवेशक गुजरा है।

उद्योग सूत्रों के अनुसार टी-30 और बी-30 शहरों में बदलाव का असर टी-30 और बी-30 से एसआईपी खातों की संख्या पर भी पड़ सकता है। मार्च से लागू हालिया बदलावों में टी-30 शहरों में दो बदलाव किए गए हैं। बी-30 पर केंद्रित एमएफ वितरण प्लेटफॉर्म जेडफंड्स के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष कोठारी ने कहा कि डायरेक्ट प्लान में बी-30 शहरों के खातों के ज्यादा बंद होने का मतलब यह नहीं है कि निवेशक फंडों से बाहर निकल रहे हैं।

उन्होंने कहा, जेडफंड्स में हम घबराहट के ठीक उलट देख रहे हैं। पिछले छह महीनों में हमारे लगभग 40 फीसदी नए निवेशक सीधे दूसरी तरफ आए हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद से शुरुआत की, उन्हें बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा और फिर उन्होंने तय किया कि कोई उनकी मदद के लिए साथ हो। सीधे निवेश से किसी की मदद लेने की ओर यह बदलाव ही इन आंकड़ों का असली संकेत है।

एसआईपी खातों पर कुछ दबाव जरूर है। लेकिन कुल एसआईपी निवेश काफी हद तक स्थिर रहा है। बी-30 से कुल निवेश फरवरी के लगभग 12,306 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल में 12,627 करोड़ रुपये हो गया।

आय अनुमान घटेंगे, बाजार की तेजी ज्यादा नहीं रहेगी

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 1 जून

बर्नस्टीन के विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर भारतीय उद्योग जगत की कमाई पर ज्यादा पड़ने की आशंका है। हाल में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि कमाई के अनुमानों में कटौती का सिलसिला फिर शुरू हो गया है और वित्त वर्ष 2027 के अनुमानों में अभी तक लगभग 3 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है।

ब्रोकरेज के अनुसार सबसे अहम कारक कच्चा तेल है। ब्रोकरेज ने कहा कि अमेरिकी-ईरान युद्ध में कमी आने और कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल या उससे नीचे जाने से कमाई पर दबाव काफी कम हो जाएगा। इससे बाजारों और राजकोषीय गणित दोनों को सहारा मिलेगा और पूंजीगत खर्च की योजनाएं भी बनी रहेंगी।

इसके विपरीत कच्चे तेल की कीमतें अगर लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो राजकोषीय और चालू खाता दोनों को ही जोखिम होगा और इसका असर आगे चलकर कमाई में बढ़ोतरी पर भी पड़ेगा। बर्नस्टीन ने कहा कि कोई भू-राजनीतिक झटका नहीं भी लगे तो भी कमाई से जुड़े जोखिम गिरावट वाले ही हैं।

बर्नस्टीन के प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल गैरे ने निखिल अरेला के साथ मिलकर लिखे नोट में कहा, 'हम निफ्टी के लिए अपना साल के आखिर का लक्ष्य 26,000 (मौजूदा स्तर से करीब 11 फीसदी ऊपर) पर कायम रख रहे हैं और अपना तटस्थ रुख बनाए हुए हैं।'

गैरे और अरेला ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 के लिए आय की रफ्तार उनके कवरेज वाले एनएसई-200 शेयरों के लिए पहले ही धीमी हो गई है। पिछले दो साल में हासिल 14 प्रतिशत की सीएजीआर के मुकाबले अब इसमें लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है।

इस पृष्ठभूमि में बर्नस्टीन ने खपत में अपना निवेश कम कर दिया है। महंगाई की चुनौतियों, सीमित नीतिगत समर्थन और ऑटोमोबाइल की मांग के चरम पर पहुंचने के संकेतों के मद्देनजर उन्होंने रोजमर्रा की चीजों (स्टैपल्स) और ऑटो सेक्टर की रेटिंग घटाकर 'अंडरवेट' कर दी है। घरेलू वृद्धि के कारकों में कमी को देखते हुए उन्होंने वित्तीय क्षेत्र को 'इक्वल वेट' श्रेणी में डाल दिया है, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर पर वह 'ओवरवेट' हैं।

लेजर पावर ने आईपीओ का आकार घटाया

इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी लेजर पावर ऐंड इन्फ्रा ने अपने प्रस्तावित आईपीओ का आकार घटा दिया है। कंपनी ने सेबी द्वारा हाल में पेश नए नियम का फायदा उठाया है। इस नियम के तहत कंपनियां विवरणिका का मसौदा दोबारा जमा कराए बिना अपने इश्यू का आकार बदल सकती हैं। शुक्रवार को कंपनी ने अपने डीआरएचपी में 16 पन्नों का एक अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराया। लेजर पावर के मूल डीआरएचपी में 1,200 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्रस्ताव था। इसमें 800 करोड़ रुपये के नए शेयर और मौजूदा शेयरधारकों का 400 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल था। नई व्यवस्था के तहत आईपीओ का आकार घटाकर 742 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 542 करोड़ रुपये के नए शेयर और 200 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल है।

सड़क परिसंपत्तियों के लिए इनविट वितरण नियमों में ढील का प्रस्ताव

सेबी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के लिए वितरण नियमों में ढील का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, सड़क-केंद्रित इनविट्स को यूनिटधारकों को वितरित की जाने वाली नकदी की गणना करते समय कर्ज के जरिये पूरे किए जा रहे बड़े रखरखाव खर्चों को भी शामिल करने की अनुमति होगी। इसका मकसद उद्योग की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दूर करना है। सोमवार को जारी परामर्श पत्र में नियामक ने प्रस्ताव किया कि इनविट्स और उनके एसपीवी को सड़क परियोजनाओं के बड़े रखरखाव खर्चों के लिए किए गए भुगतानों को वापस शामिल करने की अनुमति दी जाए। *बीएस*

घरेलू संस्थानों के रोज के आंकड़े होंगे और भी पारदर्शी

नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ने सोमवार को कहा कि वह घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के निवेश के रोजाना के रुझान जारी करना शुरू करेगा। यह पहल कस्टोडियनों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ मिलकर शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश फंडों, बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य घरेलू संस्थाओं के श्रेणी-वार निवेश के आंकड़े जारी किए जाएंगे। यह ढांचा एफपीआई के लिए मौजूदा रोजाना की डिस्क्लोजर की व्यवस्था पर आधारित है। *बीएस*

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please Scan this QR Code to view DRHP & Draft Abridged Prospectus)

amtech

AMTECH ESTERS LIMITED

(Formerly known as Amtech Esters Private Limited)

CORPORATE IDENTITY NUMBER: U24129DL2002PLC115465

Our Company was incorporated as a Private Limited Company under the name of "Amtech Esters Private Limited" under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated May 21,2002 issued by Registrar of Companies, National Capital Territory (NCT) of Delhi and Haryana, bearing CIN U24129DL2002PTC115465. Further, our Company was converted into a Public Limited Company in pursuance of a special resolution passed by the members of our Company at the Annual General Meeting held on September 30, 2023 and the name of our Company was changed from "Amtech Esters Private Limited" to "Amtech Esters Limited" & Registrar of Companies, Delhi has issued a new certificate of incorporation consequent upon conversion dated December 12, 2023, bearing CIN U24129DL2002PLC115465. For further details of incorporation please refer to section titled "Our History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 156 of the Draft Red Herring Prospectus

Registered Office: Flat No. 102, Plot No. A-3, Magnum House 1, Commercial Complex, Karam Pura, New Delhi –110015, India.
Corporate office: 2012 MIE, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana – 124507, India.
Tel: 011-49044111; **E-mail id/ Investor Grievance Mail Id:** info@amtechesters.com ; **Website:** www.amtechesters.com
Contact Person: Anjali Bansal, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: AJIT SINGH BAWA, GURPREET KAUR BAWA AND MEENAKSHI SHARMA

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR Regulations, 2018 AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE Limited ("BSE SME")

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING UP TO 23,85,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF AMTECH ESTERS LIMITED (THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. [•]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. [•] LAKHS ("THE ISSUE"). OUT OF THE ISSUE 1,20,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO RS. [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 22,65,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. [•]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [•]% AND [•]% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED REGIONAL NATIONAL DAILY NEWSPAPER (HINDI BEING THE OF REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY IS SITUATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE SME") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the **"SCRR"**) read with Regulation 229(1) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 (1) and 253 (2) of the SEBI ICDR Regulations 2018, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Portion"**), provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis **("Anchor Investor Portion")**. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. However, with effect from December 01, 2025, pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025, of which, up to 40% of the Anchor Investor Portion shall be reserved in the following manner, (i) 33.33% shall be available for allocation to domestic Mutual Funds and (ii) 6.67% shall be available for allocation to life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies, and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription under (ii) above, the allocation may be made to domestic Mutual Funds. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) **("Net QIB Portion")**. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations 2018, states that not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹ 10.00 Lakhs and two-thirds of the Non- Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount **("ASBA")** process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks **("SCSBs")** or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts.

Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled **"Issue Procedure"** on page 248 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the Regulation 247 of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification dated March 03, 2025, and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and DRHP dated May 30, 2026 which has been filed with the SME Platform of BSE Limited.

Pursuant to SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 on March 03, 2025 and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies, for fulfilling all additional eligibility criteria, the DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited **("BSE SME")** shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the BSE SME at https://www.bsesme.com/ and the website of the Company at www.amtechesters.com and at the website of BRLM i.e. Credora Partners Private Limited at www.credorapartners.com Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME) with respect to disclosures made in DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by BSE, and/or our Company and/or Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with BSE SME.

Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of investors is invited of the section titled "***Risk Factors***" beginning on Page No. 17 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME PLATFORM OF BSE LIMITED **("BSE SME")**. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see ***"Capital Structure"*** beginning on page 62 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, please refer ***"Our History and Certain Corporate Matters"*** beginning on page 156 of the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CREDORA PARTNERS ALLIANCE OF TRUST **Credora Partners Private Limited** **SEBI Registration Number:** INM000013411 **Address:** 6th Floor, B-Wing, GSC Tower, Sector- 30, Gurgaon, Haryana – 122001, India. **Telephone No:** +91-124-4293471 **Website:** www.credorapartners.com **Email ID:** info@credorapartners.com **Contact Person:** Pankaj Kumar Pasi	Maashitla Creating Successful People **Maashitla Securities Private Limited** **SEBI Registration No.:** INR000004370 **Address:** 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi- 110034, India. **Telephone No:** 011 – 47581432 **Email:** investor.ipo@maashitla.com **Website:** www.maashitla.com **Contact Person:** Mukul Agarwal	amtech **Anjali Bansal** **Address:** Flat No. 102, Plot No. A-3, Magnum House 1, Commercial Complex, Karam Pura, New Delhi –110015, India. **Tel.:** 011-49044111; **Email:** info@amtechesters.com **Website:** www.amtechesters.com Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Managers or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

FOR AMTECH ESTERS LIMITED
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Sd/-
Anjali Bansal
Company Secretary and Compliance Officer

Date: June 02, 2026
Place: New Delhi

Disclaimer: Amtech Esters Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated May 30, 2026. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/ and is available on the websites of the BRLM at www.credorapartners.com and also on the website of the ***Company*** www.amtechesters.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 17 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act'**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation"s" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.